



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 13, Issue 5, May 2024

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423



9940 572 462



6381 907 438



ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था : अतीत और वर्तमान

ओम प्रकाश कालवा¹ प्रो. प्रताप पिंजानी (से.नि.)²

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर¹

समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, केकड़ी (अजमेर)²

सारांश

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन और जटिल सामाजिक संरचना है, जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह व्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही है और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। जाति व्यवस्था की शुरुआत वैदिक काल में मानी जाती है, जहाँ समाज को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्गों का आधार कर्म और गुण थे, लेकिन धीरे-धीरे यह जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण वर्ग ने धार्मिक और शैक्षिक कार्यों का निर्वाह किया, क्षत्रिय वर्ग ने रक्षा और शासन के कार्य संभाले, वैश्य वर्ग व्यापार और कृषि में संलग्न रहा, जबकि शूद्र वर्ग ने सेवाओं और अन्य श्रम कार्यों का निर्वाह किया। समय के साथ जाति व्यवस्था अधिक कठोर और जटिल हो गई। समाज में जातियों की संख्या बढ़ती गई और उपजातियों का निर्माण हुआ। इस व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर दिया और विभिन्न जातियों के बीच असमानता को बढ़ावा दिया। उच्च जातियों को अधिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिले, जबकि निम्न जातियों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान, जाति व्यवस्था ने एक नई दिशा प्राप्त की। ब्रिटिशों ने जाति को जनगणना और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे जातियों के बीच भेदभाव और भी गहरा हो गया। इसके बावजूद, 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सुधारकों जैसे ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब आंबेडकर, और महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और सुधारों की मांग की। स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित किया और सकारात्मक भेदभाव (आरक्षण) की नीतियों को लागू किया ताकि दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर मिल सकें। आरक्षण नीति का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना और समाज में समानता स्थापित करना है। इस शोध आलेख में, हम जाति व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, और इसके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

मूल शब्द : जाति व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता, ऐतिहासिक विकास, आरक्षण नीति

परिचय :

हालांकि, जाति व्यवस्था की जड़ें अभी भी भारतीय समाज में गहरी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव अभी भी व्यापक है। कई बार जातिगत हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आती हैं। शहरी क्षेत्रों में, भले ही जाति का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया हो, लेकिन विवाह, सामाजिक मेलजोल और राजनीतिक समर्थन जैसे मामलों में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है। आज के समय में, जाति व्यवस्था पर बहस जारी है। एक ओर, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आरक्षण नीति पर भी सवाल उठते रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण के कारण समाज में नई असमानताएँ पैदा हो रही हैं, जबकि अन्य इसे सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक मानते हैं। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए सामाजिक चेतना और शिक्षा की आवश्यकता है। समाज में समानता, भाईचारा और इंसानियत की भावना को बढ़ावा देना जरूरी है, ताकि जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म किया जा सके और एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का इतिहास और वर्तमान स्थिति हमें यह सिखाती है कि सामाजिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि हम एक न्यायसंगत और समतामूलक समाज की स्थापना कर सकें।

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक प्राचीन और जटिल सामाजिक संरचना है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह व्यवस्था समाज के विभिन्न समूहों को जन्म, व्यवसाय, और सामाजिक स्थिति के आधार पर विभाजित करती है। जाति व्यवस्था न केवल सामाजिक परतें बनाती है बल्कि आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करती है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है—

प्राचीन काल :

जाति व्यवस्था का उद्भव प्राचीन भारत में हुआ। ऋग्वेद और अन्य वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें समाज को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। इस व्यवस्था का आधार कर्म और जन्म था, जहां व्यक्ति का व्यवसाय और सामाजिक कर्तव्य उसकी जाति द्वारा निर्धारित होता था।

मध्यकाल :

मध्यकाल में, जाति व्यवस्था और कठोर हो गई। सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई और जातिगत भेदभाव बढ़ गया। इस काल में विभिन्न राजवंशों और मुस्लिम आक्रमणों ने भी जाति व्यवस्था पर प्रभाव डाला, लेकिन इसका मूल ढांचा अपरिवर्तित रहा।

औपनिवेशिक काल :

ब्रिटिश शासन के दौरान, जाति व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया ताकि समाज को विभाजित रखा जा सके और अंग्रेजों का शासन मजबूत हो सके। ब्रिटिशों ने जनगणना और सरकारी दस्तावेजों में जाति को एक महत्वपूर्ण पहचान के रूप में दर्ज किया, जिससे जातिगत पहचान और मजबूत हो गई।

वर्तमान स्थिति :

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है—

संवैधानिक प्रावधान :

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई प्रावधान किए। अनुच्छेद 15 और 17 ने जाति के आधार पर भेदभाव और अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण और अन्य विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं।

सामाजिक परिवर्तन :

आधुनिक भारत में शिक्षा और आर्थिक विकास ने जातिगत विभाजनों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शहरीकरण और वैश्वीकरण ने जातिगत पहचान को कमजोर किया है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चुनौतियाँ :

जाति व्यवस्था अभी भी भारतीय समाज में मौजूद है और विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। जातिगत भेदभाव, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, एक बड़ी समस्या बनी हुई है। राजनीतिक दलों द्वारा जातिगत वोट बैंक की राजनीति भी जाति व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती है।

सामाजिक प्रभाव :

जाति व्यवस्था के सामाजिक प्रभाव निम्नलिखित हैं—

आर्थिक असमानता :

जाति व्यवस्था ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है। उच्च जातियों के पास अधिक संसाधन और अवसर होते हैं, जबकि निम्न जातियों को भेदभाव और वंचना का सामना करना पड़ता है। यह असमानता सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है और समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है।

शिक्षा और रोजगार :

शिक्षा और रोजगार में जातिगत भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है। निम्न जातियों के लोग उच्च शिक्षा और प्रतिष्ठित नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं। हालांकि आरक्षण नीति ने कुछ हद तक इस असमानता को कम किया है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है।

सामाजिक समरसता :

जातिगत भेदभाव समाज में तनाव और संघर्ष को जन्म देता है। विवाह, धार्मिक आयोजन, और सामुदायिक गतिविधियों में जातिगत बंधन अभी भी मजबूत हैं। इससे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है।

निष्कर्ष :

भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक जटिल और बहु-आयामी संरचना है जो ऐतिहासिक, सामाजिक, और आर्थिक पहलुओं से प्रभावित है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। जातिगत असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, और कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। समाज के सभी वर्गों को एकसाथ मिलकर काम करना होगा ताकि एक समान और न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके।

References:

1. Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste. Verso Books, 2014.
2. Bayly, Susan. Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge University Press, 1999.
3. Chandra, Bipan, et al. India's Struggle for Independence. Penguin Books, 1989.
4. Dirks, Nicholas B. Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India. Princeton University Press, 2001.
5. Dumont, Louis. Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications. University of Chicago Press, 1980.
6. Ghurye, G. S. Caste and Race in India. Popular Prakashan, 1969.
7. Jaffrelot, Christophe. India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India. Columbia University Press, 2003.
8. Shah, Ghanshyam, editor. Caste and Democratic Politics in India. Permanent Black, 2002.
9. Srinivas, M. N. Social Change in Modern India. Orient BlackSwan, 2017.
10. Weiner, Myron. The Politics of Scarcity: Public Pressure and Political Response in India. University of Chicago Press, 1962.
11. Zelliott, Eleanor. From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement. Manohar Publishers, 2001.



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details